छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

अंक 26 (जुलाई – सितम्बर 2024)

ईमेलः- **chhattisgarh.sccc@gmail.com** वेबसाइटः- **www.cgclimatechange.com**

मुख्य सम्पादक की कलम से..........

सम्माननीय पाठक,

मुझे त्रैमासिक न्यूज़लेटर का 26वां संस्करण प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है । इस अंक में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने हेतु सकारात्मक प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। छत्तीसगढ़ इकोरिस्ट्रेशन नीति पर कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और हितधारकों को एकत्रित किया गया ताकि हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के सतत पुनर्स्थापन के लिए एक कार्यान्वयन योग्य नीति का निर्माण किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की टीम द्वारा जल संसाधनों के प्रबंधन, सामुदायिक संरक्षण, क्लाइमेट लर्निंग लैब द्वारा जागरूकता निर्माण हेतु प्रभावशाली कार्यों के अध्ययन के उद्देश्य से केरल और मेघालय का दौरा किया गया। जिससे पर्यावरणीय संरक्षण, जलवायु अनुकूलन और जैव विविधता की रक्षा हेतु प्रयासों में मदद मिलेगी |

न्यूज़लेटर के इस अंक में हमने छत्तीसगढ़ आधारित सफलता की कहानियों को भी साझा किया है। करहनी एनिकट पर हाइड्रो मेकैनिकल पंप आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना ने किसानों के लिए फसल उपज में महत्वपूर्ण वृद्धि की है, जिससे उनकी आय बढ़ी है। एवं बिलासपुर में सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म-सिंचाई योजना ने किसानों को जल उपयोग को अनुकूलित करने और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद की है। ये सफलताएँ स्थानीय कृषि पर नवीनतम समाधानों के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती हैं।

हम आगामी न्यूज़लेटर के लिए आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का स्वागत करते हैं ।

(अरूण कुमार पाण्डेय)आई.एफ.एस.
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
तथा नोडल अधिकारी, राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र
अरण्य भवन, नवा रायपुर

विषय-वस्तु

- 31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ इकोरिस्टोरेशन नीति पर कार्यशाला आयोजन
- छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिक समृद्धि का अनावरण: बचेली वन रेंज में एक दुर्लभ वन क्षेत्र
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र टीम का CWRDM, कोझीकोड, केरल का दौरा
- छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र टीम का मेघालय का दौरा
- छत्तीसगढ़ का परिवहन विभाग: जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सराहनीय कदम
- सफलता की कहानी: करहनी एनीकट पर हाइड्रो मैकेनिकल पंप आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना
- सफलता की कहानी: बिलासपुर जिले में सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना
- एक पेड़ माँ के नाम: 80 करोड़ पौधे रोपे गए
- समाचार शीर्षक

31 जुलाई 2024 को छत्तीसगढ़ इकोरिस्टोरेशन नीति पर कार्यशाला आयोजन

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ इकोरेस्टोरेशन नीति पर दिनांक 31 जुलाई 2024 को अरण्य भवन, वन मुख्यालय, नवा रायपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य के लिए एक समावेशी और व्यावहारिक इकोरेस्टोरेशन नीति को अंतिम रूप देना था। कार्यशाला में वानिकी, खनन, कृषि, नगरीय प्रशासन और पर्यावरण जैसे विविध क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने नीति के लिए अपने विचार और सुझाव साझा किए।

कार्यशाला की शुरुआत श्री अरुण कुमार पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक इकोरेस्टोरेशन नीति की आवश्यकता पर जोर दिया, जो न केवल राज्य की पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करेगी बल्कि विभिन्न हितधारकों को भी लाभान्वित करेगी। श्री पाण्डेय ने क्षतिपूरक वनीकरण को संरक्षण प्रयासों के साथ एकीकृत करने के महत्व और हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से प्रमुख निष्कर्षों पर भी चर्चा की।

श्री वी. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख ने कार्यशाला को सम्बोधित किया। उन्होंने नीति निर्माण प्रक्रिया में आधारभूत डेटा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि नीति जनहितैषी और समावेशी होनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि नीति के परिणाम मापने योग्य और लागू करने योग्य होने चाहिए, और मौजूदा अधिनियमों, नियमों और दिशानिर्देशों के साथ संगत होने चाहिए।

तकनीकी चर्चा: तकनीकी सत्रों में वानिकी, कृषि और नगरीय पारिस्थितिक तंत्र के क्षेत्रों में प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के प्रस्तुतिकरण हुए।

श्रीमती आर. संगीता, आईएएस, सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के शहरी पर्यावरणीय चुनौतियों पर चर्चा की। उन्होंने विभिन्न उद्योगों से उत्सर्जित प्रदूषकों के प्रबंधन की तात्कालिक आवश्यकता को रेखांकित किया और यह भी कहा कि पर्यावरण प्रबंधन के लिए धन उपलब्ध है, लेकिन अच्छी योजना और गुणवत्ता कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- श्री बी. आनंद बाबू, आईएफएस, प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने सामुदायिक वन अधिकारों और वन पारिस्थितिकी तंत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए बहु-स्तरीय दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा की।
- श्री नोयल थॉमस, आईएफएस (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक केरल ने ऑनलाइन प्रस्तुति में केरल की इकोरेस्टोरेशन नीति के बारे में बताया और छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण बिंदु साझा किए। उन्होंने भूजल पुनर्भरण, कार्बन अनुक्रमण और स्थानीय समुदायों को आजीविका के अवसर प्रदान करने जैसे उद्देश्यों पर जोर दिया।
- श्री जगदीश पुप्पला राव, सीईओ, लिविंग लैंडस्केप्स, ने नीति निर्माण में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक इतिहास को ध्यान में रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्य अपनी स्वयं की एक विशिष्ट ग्रॉस नेचुरल प्रोडक्ट (जीएनपी) विकसित करे, जो उसकी पारिस्थितिकी, समाज और अर्थव्यवस्था को समाहित करे।
- श्री प्रमोद जी कृष्णन, आईएफएस, एपीसीसीएफ, केरल ने केरल की इकोरेस्टोरेशन नीति के सफल तत्वों जैसे विदेशी मोनोकल्चर और शहरी वनीकरण को बढ़ावा देने के बारे में विचार साझा किया।

कार्यशाला को वन, कृषि, शहरी, आर्द्रभूमि और खनन पारिस्थितिक तंत्र सहित चर्चाओं में विभाजित किया गया। प्रत्येक समूह, जिसमें विषय विशेषज्ञ शामिल थे, ने क्षेत्र-विशिष्ट चुनौतियों और समाधानों पर चर्चा की। इनमें वन ह्रास, जल प्रदूषण, मृदा स्वास्थ्य और अस्थिर खनन जैसे मुद्दे शामिल थे। समाधान में कृषि वानिकी, शहरी हरित स्थानों के साथ-साथ कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और नियामक रणनीतियाँ शामिल थीं।

श्री आर.के. सिंह, आईएफएस (सेवानिवृत्त), पूर्व प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने नीति निर्माण में एक एकीकृत, सहभागी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें सभी हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित हो। कार्यशाला का समापन पर्यावरणीय क्षरण का समाधान करते हुए सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ हुआ।

यह कार्यशाला छत्तीसगढ़ के सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और पर्यावरण संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को उजागर करती है।

छत्तीसगढ़ की पारिस्थितिक समृद्धि का अनावरण: बचेली वन रेंज में एक दुर्लभ वन क्षेत्र

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ ने दंतेवाड़ा वनमंडल के बचेली वन परिक्षेत्र में एक अनोखे और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण वन क्षेत्र की खोज की है। यह वन क्षेत्र, जो बीजापुर के गंगालूर वन परिक्षेत्र तक विस्तृत है, प्राचीन पौधों की प्रजातियों का निवास स्थान है और इसकी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से अपने आर्द्र और शुष्क पतझड़ी वन (वन प्रकार 3 और 5) के लिए प्रसिद्ध इस दुर्लभ वन क्षेत्र में उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले पहाड़ी वन भी शामिल हैं, जो छत्तीसगढ़ में उच्च-ऊंचाई वाले वन पारिस्थितिक तंत्र की उपस्थिति को दर्शाते हैं और संभावित रूप से राज्य का सबसे ऊँचा वन क्षेत्र है।

समुद्र तल से 1,242 मीटर से अधिक की ऊँचाई पर स्थित यह अद्वितीय वन क्षेत्र एक "जीवित संग्रहालय" के रूप में कार्य करता है, जिसमें जुरासिक युग के पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस वन की विविध वनस्पतियाँ और इसकी जटिल जैव विविधता की परतें उन पारिस्थितिक तंत्रों की झलक प्रदान करती हैं जिन्होंने सहस्राब्दियों के पर्यावरणीय बदलावों का सामना किया है। यह दुर्लभ खोज न केवल छत्तीसगढ़ के पारिस्थितिक परिदृश्य को समृद्ध बनाती है, बल्कि इन प्राकृतिक आवासों को एक अनमोल पर्यावरणीय संसाधन के रूप में संरक्षित करने के महत्व को भी उजागर करती है।

श्री अरुण कुमार पाण्डेय, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास एवं योजना एवं नोडल अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र के नेतृत्व में पारिस्थितिकीविदों और वन अधिकारियों की एक टीम द्वारा तीन दिवसीय सर्वेक्षण के दौरान इस वन क्षेत्र का पारिस्थितिक महत्व सामने आया। इस टीम में श्री एस. श्री नवीन कुमार एवं श्री वेंकटेश एम. जी. परिवीक्षाधीन आईएफएस अधिकारी के साथ-साथ वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के डॉ. राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पूर्व जीवन विज्ञान विभागाध्यक्ष श्री एम. एल. नायक जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक शामिल थे। उनके सर्वेक्षण ने कई दुर्लभ और प्राचीन पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया, जो सदियों से जलवायु चुनौतियों का सामना कर रहे इन पारिस्थितिक तंत्रों की सहनशीलता को दर्शाते हैं।

ये निष्कर्ष छत्तीसगढ़ की अनोखी पारिस्थितिक धरोहर को रेखांकित करते हैं, जो प्रकृति की सहनशीलता और संरक्षण प्रयासों के महत्व का प्रमाण है।

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र टीम का CWRDM, कोझीकोड, केरल का दौरा

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की एक टीम द्वारा अगस्त 2024 में केरल के कोझिकोड में स्थित सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (CWRDM) का दौरा किया गया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य केरल की जलवायु अनुकूलन और जल संसाधन प्रबंधन में हुई प्रगति का अवलोकन करना और ज्ञान-विनिमय के अवसरों को बढ़ावा देना था

टीम ने क्लाइमेट लर्निंग लैब का दौरा किया, जो 5,000 वर्ग फुट का एक इंटरएक्टिव स्थान है, जिसे GIZ के सहयोग से विकसित किया गया है। इसमें डिजिटल मॉड्यूल, शैक्षिक खेल और जलवायु-थीम आधारित प्रदर्शनी शामिल हैं। लैब का इंटरएक्टिव डिज़ाइन, जिसमें खेल और सेल्फी पॉइंट भी शामिल हैं, जलवायु विज्ञान में सार्वजनिक सहभागिता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है।

टीम ने जल धरोहर संग्रहालय का भी दौरा किया, जो केरल की पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों को प्रदर्शित करता है, और केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला का अवलोकन किया, जो जल गुणवत्ता, जैव प्रौद्योगिकी, और सूक्ष्म जीवविज्ञान के परीक्षण के लिए उन्नत उपकरणों से सुसज्जित है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (IISR) और मलाबार बॉटनिकल गार्डन की यात्रा ने और भी मूल्यवान जानकारियाँ प्रदान कीं। IISR की प्रसंस्करण इकाइयां मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों का समर्थन करती हैं, जबकि 40 एकड़ का बॉटनिकल गार्डन, जिसमें बटरफ्लाई पार्क और एक्वेटिक प्लांट कंज़र्वेटरी शामिल हैं, केरल के जैव विविधता संरक्षण प्रयासों को उजागर करता है।

इस यात्रा ने छत्तीसगढ़ की जलवायु अनुकूलन और जल प्रबंधन पहलों को मजबूत करने के लिए मूल्यवान सीख दी, जिससे राज्य की पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता को और प्रबल किया जा सके।

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र टीम का मेघालय का दौरा

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केंद्र की एक टीम, जिसमें श्रीमती शालिनी रैना, आईएफएस, सीसीएफ; श्री बी.पी. सिंह, वानिकी विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त सीसीएफ; और डॉ. देवयानी शर्मा, कार्यक्रम समन्वयक शामिल थे, ने 5 से 8 अगस्त 2024 तक मेघालय का दौरा किया। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य मेघालय के सामुदायिक संरक्षण प्रथाओं, जल प्रबंधन, और जलवायु अनुकूलन प्रयासों का अध्ययन था, साथ ही भारत के पहले क्लाइमेट म्यूजियम की संकल्पना का अवलोकन करना था।

इस दौरे के दौरान टीम ने मेघालय सरकार द्वारा आयोजित एक ब्रीफिंग में भाग लिया, जिसमें उन्हें राज्य की जलवायु पहलों और प्रस्तावित क्लाइमेट म्यूजियम के बारे में जानकारी दी गई। यह म्यूजियम इंटरएक्टिव प्रदर्शनों और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से जलवायु मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। मावकिनरेव और मावकिरडेप गांवों के क्षेत्रीय दौरे में टीम ने जलग्रहण पुनर्जीवन, मृदा संरक्षण, और वन प्रबंधन सहित प्राकृतिक संसाधनों के सामुदायिक-नेतृत्व वाले प्रबंधन तरीकों का अवलोकन किया। टीम ने इन प्रथाओं में पारंपरिक ज्ञान के एकीकरण का अवलोकन किया, विशेष रूप से जलवायु अनुकूलन के लिए वन प्रबंधन योजनाओं (एफएमपी) में।

एक मुख्य आकर्षण मेघालय का अनोखा ईको-टूरिज्म और संरक्षण का सम्मिश्रण था, विशेषकर योजनाबद्ध क्लाइमेट म्यूजियम और नोंगलाइल्म वन चिकित्सा क्षेत्र के माध्यम से। प्रकृति-आधारित अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान (पीईएस) मॉडल पर चर्चा ने स्थायी आजीविका और जैव विविधता संरक्षण के लिए मेघालय के प्रयासों को प्रदर्शित किया।

इस दौरे ने मेघालय की जलवायु अनुकूलन और संरक्षण-आधारित आजीविका में नेतृत्व की मूल्यवान जानकारी दी, जिससे छत्तीसगढ़ की जलवायु पहलों के लिए संभावित मार्गों को प्रेरणा मिली।

छत्तीसगढ़ का परिवहन विभाग: जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सराहनीय कदम

परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल नीतियों और सतत परिवहन समाधानों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं । वायु प्रदूषण के सबसे बड़े स्रोतों में से एक वाहन उत्सर्जन रहा है, और राज्य ने लंबे समय से इसे एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। हालिया पहलों से प्रदूषण कम करने और पर्यावरण पर उनके प्रभाव को न्यूनतम करने के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई देती है।

स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस)

गुजरात के बाद, छत्तीसगढ़ ऑटोमैटिक फिटनेस सेंटर (एटीएस) संचालित करने में भारत में दूसरा स्थान रखता है। राज्य में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की फिटनेस और पर्यावरण-अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशनों (एटीएस) की स्थापना की गई है। आठ अनुमोदित स्थानों में से सात पहले से ही रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा और राजनांदगांव में संचालित हो रहे हैं, जबकि एक अन्य रायगढ़ में निर्माणाधीन है। जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक, इन स्टेशनों से कुल 49,390 वाहनों को लाभ हुआ है, जिनमें दुर्ग में 24,268, बिलासपुर में 10,608, कोरबा में 7,671, जगदलपुर में 3,740 और राजनांदगांव में 3,103 वाहनों की फिटनेस जांच की गई। ये स्वचालित स्टेशन समय पर और व्यापक तकनीकी फिटनेस जांच प्रदान करते हैं, जिससे मैन्युअल निरीक्षण पर निर्भरता कम होती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि वाहन आवश्यक उत्सर्जन मानकों को पूरा करें, प्रदूषण घटाएं और सुरक्षित, अधिक सतत परिवहन विकल्पों को बढ़ावा दें।

पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ)

प्रदूषण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पुराने और अनुपयुक्त वाहनों की समस्या को हल करने के लिए परिवहन विभाग ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) शुरू की हैं। ये सुविधाएं वाहन मालिकों को पुराने वाहनों को स्क्रैप करने और नए वाहनों की खरीद पर कर छूट प्राप्त करने की अनुमति देती हैं। यह सुविधा रायपुर में पहले से शुरू की जा चुकी है और जगदलपुर, दुर्ग, बिलासपुर और रायगढ़ में विकासाधीन हैं, जिससे प्रदूषणकारी, पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने और उत्सर्जन को कम करने में प्रोत्साहन मिलता है।

इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022

इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने और प्रदूषण को रोकने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह नीति मार्च 2027 तक मान्य है और छत्तीसगढ़ को इलेक्ट्रिक गतिशीलता में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन खरीदारों को उदार सब्सिडी प्रदान की जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को ₹1.5 लाख तक की सब्सिडी मिल सकती है, जबकि हाइब्रिड वाहन खरीदारों को ₹75,000 तक की सब्सिडी दी जाती है। अब तक, 31,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदार ₹55 करोड़ की कुल सब्सिडी का लाभ उठा चुके हैं। इस नीति के कार्यान्वयन के बाद से ईवी अपनाने की दर दोगुनी हो गई है, पंजीकरण 36,329 से बढ़कर 78,016 हो गया है। इसके अतिरिक्त, ईवी मालिकों को पंजीकरण के पहले दो वर्षों में 100% तक कर राहत सहित महत्वपूर्ण कर छूट मिलती है।

प्रदूषण नियंत्रण उपाय

उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए विभाग ने राज्य में 461 प्रदूषण परीक्षण केंद्र स्थापित किए हैं। ये केंद्र यह सुनिश्चित करते हैं कि वाहन केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार नियमित रूप से उत्सर्जन परीक्षण कराएं। हाल ही में प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली को वाहन 4.0 और एमपरिवहन ऐप के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे यह प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है और रीयल-टाइम अपडेट और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। इन प्रणालियों का कार्यान्वयन वाहन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण रहा है, जिससे पूरे छत्तीसगढ़ में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

निष्कर्ष

परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य के जलवायु परिवर्तन चुनौतियों से निपटने हेतु सराहनीय प्रयास किये जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की स्थापना और पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं की शुरुआत जैसी नवीन पहलों के माध्यम से विभाग सतत परिवहन को बढ़ावा देने और राज्य के वाहन जनसंख्या के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये प्रयास न केवल स्वच्छ वायु और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करते हैं, बल्कि राज्य की एक हरित और अधिक स्थायी भविष्य की प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

(स्रोतः परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)

DID YOU KNOW?

एक पेड़ माँ के नाम

"22 सितम्बर 2024 को जैसलमेर में "विशेष पौधारोपण अभियान" .

विश्व रिकॉर्ड बनाया :

- एक घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे।
- एक घंटे में महिलाओं की एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे।
- एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा पौधारोपण।

(स्रोतः पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार)

सफलता की कहानी: करहनी एनीकट पर हाइड्रो मैकेनिकल पंप आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना

परिचय

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बेंगलुरु द्वारा डिज़ाइन और विकसित की गई हाइड्रो मैकेनिकल पंप आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना सिंचाई के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इस प्रणाली में चार मुख्य घटक शामिल हैं: एक टरबाइन पंप, एक रैम पंप, एक स्टोरेज टैंक, और एक फील्ड चैनल। विशेष रूप से, इस प्रणाली का संचालन बिजली या सौर ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता है, जो इसे एक स्थायी सिंचाई समाधान बनाता है।

स्थान

यह योजना छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के करहानी गांव में सोन नदी पर स्थित करहानी एनीकट पर लागू की गई है। यह रणनीतिक स्थान स्थानीय जल संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करता है, जिससे क्षेत्र के किसानों को आवश्यक सिंचाई सहायता मिलती है।

परिणाम

इस परियोजना की सिंचाई क्षमता खरीफ और रबी मौसम में 100 एकड़ और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए 50 एकड़ कवर करने के लिए डिज़ाइन की गई है। करहानी गांव के कुल 56 किसान इस पहल से लाभान्वित हुए हैं। इस योजना के कार्यान्वयन से पहले औसत फसल उत्पादन प्रति एकड़ लगभग 10-15 क्विंटल था। हालांकि, हाइड्रो-मैकेनिकल प्रणाली के परिचय के बाद, उत्पादन बढ़कर प्रति एकड़ 25 क्विंटल हो गया है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि के परिणामस्वरूप किसानों की आय में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी कमाई 31,000 से 46,500 के बीच हो गई है।

निष्कर्ष

हाइड्रो मैकेनिकल पंप आधारित लिफ्ट सिंचाई योजना करहानी के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास साबित हुई है। यह योजना खरीफ, रबी, और ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए फसल वृद्धि का समर्थन करती है। इस अभिनव योजना के निर्माण और संचालन में शामिल अधिकारियों की संतुष्टि इसके स्थानीय कृषि समुदाय पर सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है।

(स्रोत: जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)

सफलता की कहानी: बिलासपुर जिले में सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई योजना

परिचय

सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो-सिंचाई योजना जल उपयोग को अनुकूलित करने के लिए ड्रिप सिंचाई के सिद्धांतों का उपयोग करती है। इस पद्धति में विभिन्न आकारों और जल-प्रवाह क्षमता वाले पीवीसी और एचडीपीई पाइपों का उपयोग किया जाता है, जो फसलों की जड़ों तक सीधे पानी पहुँचाते हैं। प्रणाली के प्रमुख घटकों में मोटर पंप, फ़िल्टर यूनिट, फर्टिगेशन यूनिट, और ड्रिपर्स और प्रेशर गेज से सुसज्जित पाइपलाइन शामिल हैं, जो उच्च सिंचाई दक्षता प्रदान करते हैं।

स्थान

यह माइक्रो-सिंचाई योजना छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मस्तुरी ब्लॉक में मल्हार और मनेदरा गांवों के बीच स्थित है। यह स्थान स्थानीय सौर ऊर्जा का लाभ उठाते हुए क्षेत्र में सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देता है।

परिणाम

यह योजना मल्हार में 40 हेक्टेयर और मनेदरा में 20 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई के लिए डिज़ाइन की गई है। किसानों की सफलता की कहानियाँ इस योजना के प्रभाव को दर्शाती हैं:

मल्हार के श्री नवीन अग्रवाल ने 2.5 एकड़ कृषि भूमि में 1.20 लाख का निवेश किया और 2023 की गर्मी की फसल के दौरान लगभग 1 लाख का लाभ प्राप्त किया।

मनेदरा के श्री मान सिंह ने 58,000 का निवेश किया, जिससे 1,45,000 का कुल कारोबार हुआ और उसी मौसम में 87,000 का लाभ प्राप्त हुआ।

निष्कर्ष

मल्हार और मनेदरा के किसानों के लिए सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो-सिंचाई योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसानों द्वारा व्यक्त की गई प्रसन्नता इस योजना की सफलता को दर्शाती है और कुशल खेती की प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इसकी भूमिका को रेखांकित करती है। सीमित जल उपलब्धता के बावजूद, यह अभिनव दृष्टिकोण दर्शाता है कि सतत और उत्पादक कृषि संभव है।

(स्रोतः जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन)

एक पेड़ माँ के नाम: 80 करोड़ पौधे रोपे गए

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरुआत की थी। यह अभियान पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व निभाने के साथ-साथ माताओं के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव दर्शाने की एक अनूठी पहल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 5 जून, 2024 को दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान की शुरुआत की थी।'एक पेड़ माँ के नाम' एक संकेतिक भाव है अपनी माँ के नाम पर एक पेड़ लगाने का उद्देश्य जहां, जीवन को पोषित करने में माताओं की भूमिका का सम्मान करना है, वहीं अपने ग्रह को स्वस्थ बनाए रखने में अपना योगदान देना भी है। पेड़ जीवन को बनाए रखते हैं और एक माँ की तरह ही पोषण, सुरक्षा और भविष्य प्रदान करते हैं।

80 करोड़ पौधा रोपण

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सितंबर 2024 तक 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने के अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा किया। यह लक्ष्य तय समय सीमा से 5 दिन पहले यानी 25 सितंबर 2024 को ही हासिल कर लिया गया। मंत्रालय की यह उपलब्धि सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों और विभिन्न हितधारकों के सहयोग और प्रयासों का परिणाम है।

5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड

22 सितंबर 2024 को, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत प्रादेशिक सेना की 128 इन्फेंट्री बटालियन और पारिस्थितिकी कार्य बल इकाई ने सिर्फ़ एक घंटे में 5 लाख से ज़्यादा पौधे लगाकर एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। जैसलमेर में "विशेष पौधारोपण अभियान" के अंतर्गत यह शानदार उपलब्धि, प्रधानमंत्री के "एक पेड़ माँ के नाम" और प्रादेशिक सेना की पहल, "भागीदारी और ज़िम्मेदारी" का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी को यथास्थिति में बनाए रखना और स्थानीय समुदायों के बीच पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। प्रादेशिक सेना की इकाई के इन प्रयासों को वर्ल्ड बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स, लंदन द्वारा निम्नलिखित विश्व रिकॉर्ड के साथ मान्यता दी गई :

- एक घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे।
- एक घंटे में महिलाओं की एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज़्यादा पौधे।
- एक ही स्थान पर एक साथ सबसे अधिक संख्या में लोगों द्वारा पौधारोपण।

(स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार)

समाचार शीर्षक

Unveiling C'garh's ecological richness

A rare forest patch in Bacheli forest range in Dantewada

Staff Reporter
RAIPUR, Sept 12

IN A remarkable finding, the Forest and Climate Change Department, Chhattisgarh recently identified a rare and ecologically significant forest patch in the Bacheli forest range of Dantewada forest division, extending into the Gangalur forest range of Bijapur. This unique forest, home to several ancient plant species, showcases the state's exceptional biodiversity and deepens the understanding of its ecological wealth.

Situated at an altitude of more than 1,242 meters sea level (MSL), this forest is classified as a subtropical broad-leaved hill forest (Forest Type 8). Notably, this may perhaps be the highest-altitude forest hill in Chhattisgarh.

While the state is primarily known for its Moist and Dry Deciduous forests (Forest Types 3 and 5), this recent finding introduces a new ecological dimension. The area is regarded as a 'Living Museum,' preserving plant species that date back to prehistoric times, possibly even to the Dinosaur era. Some plant species identified here are believed to be recorded in Chhattisgarh for the first time.

This discovery underscores the intricate layers of biodiversity that have persisted for millions of years, surviving significant environmental changes. It enriches Chhattisgarh's ecological narrative and serves as a testament to the resilience of nature, preserving life through millennia.

The findings emerged from a three-day survey led by Additional PCCF (Development & Planning) Arun Kumar Pandey alongside a team of ecologists and forest officials. The team included IFS probationers S. Naveen Kumar and Venkatesha M.G., renowned scientists such as Dr Rajendra Prasad Mishra, Deputy Director from the Wildlife Trust of India (WTI), and M.L. Nayak, former Head of the Department (School of Life Sciences) at Pt. Ravi Shankar Shukla University, Raipur. Devyani Sharma and Anurag Gupta from the Forest Department were also part of the team.

During the survey, the team documented an astonishing variety of rare and ancient plant

(Contd on page 6)

Additional PCCF Arun Kumar Pandey with other forest officials.

सम्पादक मंडल

- श्री अरूण कुमार पाण्डेय, I.F.S (मुख्य संपादक)
- डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव
- डॉ देवयानी शर्मा
- श्री अभिनव कुमार अग्रहरी

छत्तीसगढ़ राज्य जलवायु परिवर्तन केन्द्र

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ

अरण्य भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19

नवा रायपुर, छत्तीसगढ

ईमेल : chhattisgarh.sccc@gmail.com

वेबसाइट : www.cgclimatechange.com